tific institution, he actually employed a team of scientists; and instead of the team of scientists going to the institutions, which they were supposed to cater, he is right that they were located in Delhi and we don't know what scientific work was going on there. Therefore, when we enquire into the matter we will take all these aspects into account, including the one which the hon. Member has made a reference to.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA : The hon. Finance Minister is considering the assets created by Brahmchari I would invite his attention to the fact that in the State of J & K in Udhampur, the Brahmchari has occupied forest land measuring over 200 kanals and State land measuring over 150 kanals, on which he has built properties worth crores of rupees. I would like to know for the purchase of all this property, from where that money came. I would also like to know whether that income was at all assessed and what is the source thereof ? That should be inquired into.

PROF. MADHU DANDAVATE : I think I have given a general assurance that we will inquire in depth into all the financial assets of Brahmchari.

MR. CHAIRMAN : Now, he assures you.

Recommendation of the Falta Export processing zone advisory committee on export processing zones

*203. SHRI SHIV PRATAP MISHRA† :
DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether the Falta Export Processing Zone Advisory Committee had, at its first meeting held on July 3, 1990, urged the Central Government to bring about some policy modifications so as to extend more incentives for Export Processing Zones ; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU) : (a) and (b) Two meetings of the Advisory Committee set up for the Falta Export Processing Zone have been held, one on July 13, 1990 and another on August 4, 1990. Formal proposals from the Development Commissioner on the recommendations of the Committee are awaited.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: To boost up the country's exports and earn more foreign exchange, what are the detailed incentives recommended by Export Processing Zone Committee and what action has been taken thereof ?

SHRI ARUN KUMAR NEHRU : As I mentioned earlier, its meetings were held on 13th of July and on 4th of August. Only on 20th of August we have received the recommendations. We have asked the Development Commissioner to give his comments. I say so because it is after we receive the comments of the Development Commissioner, that we will have a meeting of the Committee of Secretaries, which involves many Ministries. Then the Commerce Ministry will take a view. I have, however, got a copy of their report. I can also give answer as to what we are planning to do. But I think it would be a little premature to do that. So, we should wait for the comments of the Development Commissioner, because that is the procedure.

SHRI SHIV PRATAP MISHRA: May I know from the Minister whether the Government proposes to set up more export processing

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shiv Pratap Mishra.

zones in the country ? If so, what are the details thereof ?

SHRI ARUN KUMAR NEHRU : Sir, there are already six export zones and if we analyse over the last three or four years, they have done reasonably well. Our turnover has gone up from nearly Rs. 320 crores in 1985, we estimate, to about Rs. 1000 crores. We have also approached the State Governments if we get any proposals for setting up of additional zones; we will consider them favourably. But at the present moment, we have got FALTA and we are also examining Vizag but if we have valid proposals from the States we will consider them favourably.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 13 जुलाई और 4 अगस्त की फैल्टा निर्यात संवर्धन क्षेत्र के लिये स्थापित सलाहकार समिति की जो बैठक हुई, उसकी सिफारिशों पर इनके विकास आयुक्त से कब तक पूर्ण रूप से विवरण आ जायेगा और कब तक इस मामले को वे कानून के रूप में लागू करेंगे ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि फैल्टा एक्सपोर्ट जोन पिछले दो तीन साल में कितनी प्रगति कर चुका है एक्सपोर्ट के क्षेत्र में और पिछले तीन सालों में इसने कितना एक्सपोर्ट किया है और कितनी मशीनरी या रा मेटीरियल का इंपोर्ट किया गया है ।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों एक्सपोर्ट इंसेंटिव बन्द किया गया है क्योंकि जब तक हम इंसेंटिव नहीं देंगे तब तक विदेशों में हमारा निर्यात पूर्ण रूप से नहीं हो पायेगा और जो इंसेंटिव इस सरकार ने रोक दिया है उसको एक न एक दिन चालू करना होगा, बिना इसके एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं सकते ?...

श्री सभापति : आप इंसेंटिव की बात करिये, बहुत लम्बा सवाल मत करिये...
(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैं जानना चाहता हूं कि अभी भारत के भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री देवीलाल जी ने आरोप लगाया हमारे माननीय मंत्री जी पर कि उन्होंने कमीशन लिया है । हो सकता है की यह झूठ हो, लेकिन...

श्री सभापति : फैल्टा में ?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि इंसेंटिव डीलिंग में क्या कोई कमीशन की बात चल रही है, इसलिये डिले किया जा रहा है और एक्सपोर्ट का नुकसान हो रहा है ? मैं विश्वास करता हूं कि हमारे मंत्री जी कमीशनखोर नहीं हैं। तो क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस कमीशन के नाम पर इंवाल्व तो नहीं हैं, यह मैं जानना चाहता हूं...

SHRI MENTAY PADMANABHAM: That should be expunged. It should not go on record.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Chairman, Sir, you cannot permit it.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महोदय, न मैंने कोई असंसदीय बात कही है, न कोई असत्य कहा है, न कोई अतथ्य कहा है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कमीशनखोर हमारे मंत्री नहीं हैं। लेकिन इस तरह का आरोप भारत के भूतपूर्व उप-प्रधान मंत्री ने लगाया है। तो और लोग तो नहीं खा रहे हैं, कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह तो नहीं हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अरुण नेहरू : सभापति महोदय, पहली चीज तो यह है कि जो कुछ सुझाव आये हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर अपनी रपोर्ट दे देंगे तो उसके बाद ही उन पर कार्यवाही की जायेगी।

दूसरा चार्ज फैल्टा में जो ऐक्सपोर्ट जोन है, 1984-85 में वहां पर वह स्थापित किया गया था और आंकड़े जो हैं उनके अनुसार पहले साल में 2 करोड़ का ऐक्सपोर्ट हुआ था और पिछले तीन सालों का परफार्मेंस देखिये तो 8 करोड़ का, 16 करोड़ का और इस साल के सात महीनों में साढ़े तेरह करोड़ का ऐक्सपोर्ट किया गया है। तो ट्रेड इसमें अच्छा है। दूसरा चार्ज आपने यह है कि इंसेंटिव विदड्रा किये गये हैं। कोई इंसेंटिव विदड्रा नहीं किया गया है। एक सजेशन यह आया है कि फैल्टा में इंसेंटिव और देने चाहिये। मगर जो भी हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट यूनिटस हैं उसमें कोई इंसेंटिव विदड्रा नहीं किया गया है। मगर एक समस्या सबके सामने आ रही है कि एक्सपोर्ट जोन में थोड़े से इंसेंटिव सरकार ने जो दिये हैं और जो डामेस्टिक ट्रेफिक एरिया होता है उसमें भी ... (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : बनारस में गलीचों का एक्सपोर्ट होता है। उसमें इंसेंटिव कोई नहीं मिल रहा है।

SHRI ARUN KUMAR NEHRU: The hon. Member should understand the subject. You can either talk about Falta and 100 per cent export zone or you can talk about domestic area at Varansi and other exports. He has to get his priority right. I can assure you that there is no phosphoric acid in Falta. You know it is a couple of thousand miles away. But I would suggest that if he does his homework and ask whatever he wants, we are willing to answer.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अरुण कुमार नेहरू : वह भी जवाब दे दिया है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : नहीं दिया है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि फैल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के निर्माण के समय जो परिकल्पना की गई थी कि वह परिकल्पना अभी तक 10 परसेंट भी पूरी नहीं की गई है। और उसे सिर्फ निजी पूंजी के इंसेंटिव के आधार पर छोड़ दिया गया है इसलिये क्या सरकार ऐसी वस्तुओं की जिनके निर्यात की संभावना है, अपनी तरफ से कोई पहल कदमी बनाने की योजना बना रही है या नहीं बना रही है?

श्री अरुण कुमार नेहरू : पहली चीज तो यह है कि फैल्टा के बारे में जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें आपने देखा होगा कि पिछले तीन सालों में एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया है। मगर जो भी कोई हंड्रेड पर्सेंट एक्सपोर्ट जोन होता है उसमें कोई पब्लिक सेक्टर द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपने यूनिटस नहीं लगते हैं। वहां प्राइवेट सेक्टर को ही एनकरेज करना पड़ता है। यह जो दोनों कमेटियों की रिपोर्ट आई है उसमें इंसेंटिव के विषय में काफी कहा गया है और दूसरी चीज यह भी कही गई है कि जो प्रदेश सरकारें हैं उनको वहां काफी काम करना है। इस वक्त केन्द्रीय सरकार की तरफ से 16 करोड़ रुपये वहां खर्च किये जा चुके हैं।

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Mr. Chairman, Sir, I have had an opportunity to look into the working of this export promotion zone, particularly Falta. I personally visited a couple of years back. The concept of export promotion zone is valuable. I am not really in agreement with the hon. Minister when he is giving a very encouraging picture. I presume, maybe things are moving ahead.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Unless I say some background things...

MR. CHAIRMAN: Don't go so long.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Then I can withdraw.

MR. CHAIRMAN: Okay.

Estimated demand of steel by the year 2000

*204. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what is the estimated demand of steel by the year 2000;

(b) what is the capacity of the integrated steel plants and the secondary steel sector at present;

(c) what is the optimum economic capacity of the integrated steel plants;

(d) whether after expansion of the integrated steel plants and expansion of the existing large plants in the secondary sector, Government expect a gap between demand and supply as projected for the year 2000; and

(e) whether in view of the above, Government feel the need to allow new steel plats to come up rather than expanding the existing ones?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The VIII Plan Working Group on Iron & Steel has estimated the total demand for finished steel for the year 1990-2000 as 31 million tonnes.

(b) The current achievable capacity of the integrated steel plants is as under:

(Crude Steel in million tonnes)

Plant	Achievable capacity
Bhilai	4.00
Durgapur	1.15
Rourkela	1.40
Bokaro	4.00
IISCO	0.37
TISCO	2.40

The Vizag Steel Plant (capacity of 3 MT per annum) will come on stream in 1992.

The total electric steel making capacity in the secondary steel sector for which industrial licences have been issued is 6.36 MTs.

(c) The optimum economic capacity of integrated steel plants will vary depending upon a varity of factors such as location, product-mix, infrastructure cost etc. It is unlikely that a conventional integrated steel plant will be viable financially if it is of a capacity of less than 1.50 to 2.00 million tonnes per annum in our country.

(d) Yes, Sir.

(e) Both expansion and new steel projects are necessary.

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, the Minister has laid a statement on the Table of the House. The basic thrust of the question is the gap between demand and supply of steel. The Minister himself has said an integrated steel plant at 2 million tonnes capacity would become viable. Sir, my first question is, has the Government chalked out a plan to expand the public sector steel plants to-